एक हजार उद्योगों के लिए भूमि की व्यवस्था पक्की

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआइएस) में हासिल 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतरने की कोशिशों में जुटी योगी सरकार निवेशकों से हुए करार (एमओयू) के तहत उन्हें जमीन उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में अब तक एक हजार से अधिक इकाइयों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है, वहीं दो के आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य सरकार ने 22 हजार से अधिक निवेश करार किए थे, इनमें 1450 एमओयू के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में सर्वाधिक भूमि की मांग है। हालांकि, मांग के सापेक्ष सबसे अधिक भूमि लखनऊ में उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। लखनऊ में 72 एमओयू के लिए भूमि की मांग की गई, जिसके सापेक्ष सर्वाधिक 46 की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।

इसी तरह अलीगढ़ में 51 में से 42, आजमगढ़ में 43 में से 42, जौनपुर में 44 में से 40, गौतमबुद्धनगर में 93 में से 36 और मेरठ में 44 में से 32 प्रोजेक्ट के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 157 निवेशकों ने भूमि की मांग की है, जिसके सापेक्ष फिलहाल 18 की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT
10-12 FEBRUARY, 2023

- उद्यमियों की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराई जा रही भूमि
- गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में सर्वाधिक भूमि की मांग

इन जिलों में उपलब्ध है मांग के अनुरूप भूमि

लखनऊ के अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां मांग के अनुरूप 100 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। इनमें फतेहपुर में 19, मऊ में 10, चंदौली में 12, हमीरपुर में 11, महोबा में 11, अंबेडकरनगर में 10, फर्रुखाबाद में पांच, श्रावस्ती व सिद्धार्थनगर में चार-चार, बलिया में तीन, कौशांबी में दो, लखीमपुर खीरी में दो और पीलीभीत में एक शामिल हैं। प्रदेश में कन्नौज एकमात्र जिला हैं, जहां किसी भी उद्यमी ने भूमि की मांग नहीं की है।